भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **382**
दिनांक **24** जून, 2019

हाइड्रोकार्बन के कुएँ

382. श्री ए॰ राजाः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) त मलनाडु सहित देशभर में खोदे जाने वाले हाइड्रोकार्बन कुओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) त मलनाडु सहित देश भर में इन खुदाइयों के लए निवेश कए जाने वाली संभा वत नि ध का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस खुदाई गति व धयों से अधोस्तरी मृदा के प्रभा वत होने और तटरेखा, वशेषकर त मलनाडु, की वशेषताओं में परिवर्तन होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या त मलनाडु सहित कुछ राज्यों ने अपनेक्षेत्रों में इन खुदाइयों पर आपत्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): वर्ष 2019-20 में देश भर में वे धत कए जाने वाले हाइड्रोकार्बन कूपों के ब्यौरे त मलनाडु सहित राज्य/यूटी-वार और इन वेधनों में निवेश की जाने वाली धनरा श निम्नानुसार है:-

राज्य	वे धत कए जाने वाले कूप (सं.)
आंध्र प्रदेश	28
असम	83
अरुणाचल प्रदेश	2
राजस्थान	107
मध्य प्रदेश	2
गुजरात	232
त्रिपुरा	21
झारखंड	24
पश्चिम बंगाल	2

त मलनाडु	23
अपतट	181
योग	705

इन कूपों को वे धत करने के लए लगभग 31,996 करोड़ रुपए की धनरा श का नवेश कए जाने की संभावना है।

(ग): कोई भी वेधन कार्यकलाप करने से पहले, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) लेनी अनिवार्य है। ईसी प्राप्त करने के लए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करना पूर्व शर्त है। ईआईए रिपोर्ट प्रस्ता वत वेधन परियोजना से होने वाले पर्यावरणीय पहलुओं और प्रभावों का पता लगाती है और उसके प्रभाव को कम करने के उपायों का सुझाव देती है।

(घ) और (ड.): त मलनाडु में कुछ स्थानीय लोगों/संगठनों ने क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों के वरुद्ध राष्ट्रीय हरित अ धकरण (एनजीटी) में या चका दायर की है। नागालैंड राज्य में राज्य सरकार की अनुमति के अभाव में अन्वेषण कार्यकलाप रुके हुए हैं। पुद्दुचेरी संघ शा सत प्रदेश की सरकार ने भी पद्दुचेरी और कराइकल क्षेत्र में अन्वेषण कार्यकलाप करने की अनुमति देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है जिसका कारण स्थानीय लोगों द्वारा वरोध करना बताया है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ओएनजीसी ने व भन्न स्थानीय प्रचार माध्यमों के जरिए सूचना प्रसारित करके पर्यावरणीय गरावट के बारे में लागों की आशंका को दूर कया है। मथेन/ोल गैस, भूजल के कम होने/प्रदूषण, कृ ष भू म पर प्रभाव, अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) कार्यकलापों की जटिलताओं, प्रौद्यो ग कयों सां व धक आवश्यकताओं आदि के संबंध में व भन्न भ्रान्तियों पर स्पष्टीकरण राज्य सरकार और स्थानीय लोगों को दिया गया।

****